उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दीपावली-होली पर मुफ्त सिलिंडर के वादे पर सरकार आगे बढ़ी है। बजट में 3047 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

$1 ट्रिलियन इकॉनमी

तय आय सीमा वाले अभिभावकों की निजी स्कूल में पढ़ रहीं दो बेटियों में एक की फीस का खर्च सरकार उठाएगी। 5 करोड़ रुपये बजट में दिए गए हैं।

इन्फ्रास्ट्रक्चर की उड़ान को ईंधन

₹1 लाख 62 हजार करोड़ से अधिक खर्च होंगे बुनियादी विकास पर

Premshanker.Mishra@timesgroup.com

लखनऊ : यूपी के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को सदन में 6.90 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। योगी सरकार 2.0 का यह दूसरा बजट आकार में सबसे बड़ा और पिछली बार से करीब 12% ज्यादा है। बावजूद इसके नई घोषणाएं कम हैं और इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित विकास योजनाओं के लिए आवंटन करीब डेढ़ गुना बढ़ गया है। सरकार ने बखूबी समझा है कि यूपी को वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने और 33.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के जमीनी अमल का रास्ता बुनियादी विकास से होकर ही गुजरेगा इसलिए इस पर 1.62 लाख करोड़ से अधिक खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। विकास की डोर से हर छोर को जोड़ने के लिए शहर से खेत तक चिंता दिखी है तो पढ़ाई और दवाई का ढांचा बेहतर बनाने की ओर भी कदम बढ़े हैं।

वित्त मंत्री ने बजट की भूमिका रखते हुए कहा, 'फकत किनारे बैठे-बैठे/लहरों से मत सवाल कर/डूब के खुद गहरे पानी में/पानी का फलसफा समझ।' बजट की तस्वीर भी उम्मीदों व हकीकत के फलसफे को समझते हुए तैयार की गई है। पिछले बजट में 39 हजार करोड़ रुपये की नई योजनाएं थीं, इस बार इनका आकार घटकर 32 हजार करोड़ रुपये हो गया है।

'दान' व ज्ञान दोनों पर ध्यान

सबसे अधिक युवा आबादी प्रदेश की पूंजी भी है और सियासी आकांक्षाओं का केंद्र भी इसलिए बजट में इनकी उम्मीदों को संवारने पर खास जोर है। युवाओं को मुफ्त टैबलेट/स्मार्टफोन बांटने का बजट ढाई गुना बढ़ा है। मुरादाबाद, मीरजापुर व देवीपाटन मंडल में नए राज्य विश्वविद्यालय खुलेंगे। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि एवं प्रौद्योगिक विवि बनेगा। स्टार्टअप, स्किल डिवेलपमेंट जैसी रोजगारपरक योजनाओं में भी बजट बढ़ा है। बेसिक व माध्यमिक स्कूलों का जहां ढांचा बदलेगा, वहीं गांवों में 300 करोड़ रुपये खर्च करके डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की जाएगी। संस्कृत विद्यालयों के विकास पर भी 100 करोड़ खर्च होंगे और वहां पढ़ने वालों की स्कॉलरशिप और बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेजों से अछूते 14 जिलों को भी इनसे जोड़ने के लिए 2400 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। फार्मा का भी नया इंस्टिट्यूट बनेगा।

> **योगी सरकार ने पेश किया ₹6.90 लाख करोड़ का बजट, 14 लाख से अधिक किसानों को नलकूपों पर फ्री बिजली**

ताकि सुरक्षित रहे 'फसल'

विधानसभा चुनाव में छुट्टा पशुओं के खेत के साथ ही 'वोट' चरने की आशंका को देखते हुए मोदी-योगी ने इस समस्या के समाधान का वादा किया था। इस पर 700 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। 14 लाख से अधिक किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली के वादे के अमल की ओर भी सरकार बढ़ी है। वहीं, ग्रामीण आवास योजनाओं का बजट करीब 2,700 करोड़ रुपये बढ़ा है। खेत-खलिहान संग शहरों को चमकाने के लिए 3,500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे।

पर्यटन व आस्था का समन्वय

बजट में विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा गया, 'प्रदेश में ऐसा माहौल बना दिया गया था कि अपनी धार्मिक आस्था को प्रकट करना अपराध की श्रेणी में आ गया था।' इसकी बदली तस्वीर को रेखांकित हुए आस्था व राष्ट्रवाद के सरोकार को गाढ़ा करने की कवायद भी दिखी है। धार्मिक नगरों को सड़कों से जोड़ने, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, अयोध्या, काशी, चित्रकूट, प्रयागराज, विंध्य, शुकतीर्थ, नैमिषारण्य सहित अन्य धार्मिक नगरों के लिए खजाना खुला है। शहीदों के स्मारक व प्रेरणा स्थल बनाने के लिए भी बजट प्रावधान है। 'बुलडोजर नीति' जारी रहेगी और इसके लिए पुलिस और संसाधनों से लैस की जाएगी। वित्तमंत्री ने कहा भी, 'सेनानी! करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है; ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है।'

संकल्प पत्र के 110 वादे ज़मीन पर उतारेः योगी

सीएम बोले- $1 ट्रिलियन इकॉनमी की राह में बजट मील का पत्थर

■ एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ

2022 विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे। उन 130 वादों में से 110 को जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने बजट में व्यवस्था की है। विधानसभा में 6.90 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस से बात करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संकल्प पत्र के वादों को मूर्त रूप देने के लिए बजट में 64,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। ये वादे पूरे करने की हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता है। यह बजट यूपी को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने और एक ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।

बिना टैक्स बढ़ाए विकास कार्यों को दी रफ्तार

सीएम ने बताया कि कैसे 2017 में सत्ता में आने के बाद हर साल खास लक्ष्यों पर केंद्रित बजट प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रदेश का चौमुखी विकास हो सके। सत्ता में आने के बाद टैक्स चोरी रोकने और वित्तीय प्रबंधन पर काम किया गया। इसी का नतीजा है कि बिना टैक्स में बढ़ोतरी किए प्रदेश में विकास कार्यों को रफ्तार दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बजट का लगभग 8% हिस्सा पुराने ऋण के बकाये में चला जाता था, जिसे घटाकर अब 6% कर लाया गया है। यूपी की बेरोजगारी दर जो 2016-17 में 17-18% थी, अब 4% तक रह गई है। 2016-17 में राज्य कर का राजस्व 86 हजार करोड़ था, जो 2022-23 में बढ़कर 2 लाख 22 हजार करोड़ रुपये तक होने का अनुमान है। 2016-17 में स्टेट एक्साइज के रूप में 14,277 करोड़ रुपये मिले थे, जो इस वित्तीय वर्ष में 49 हजार करोड़ से अधिक तक पहुंचने का अनुमान है।

'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश'

सीएम ने कहा कि सरकार ने अपने हर बजट में एक थीम को लेकर योजनाबद्ध ढंग से प्रयास किया। इस बार 2023-24 के बजट की मूल भावना आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश है। सीएम ने कहा कि पिछले 6 साल में बजट में में दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई है। इस दौरान प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक हुई है। वहीं बजट में जो घोषणाएं हुई हैं, उसमें मुख्य रूप से प्रदेश में एक बड़ा भाग पूंजीगत व्यय के लिए है, यानी प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास पर यह राशि खर्च होगी, जो प्रदेश में रोजगार सृजन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगी।

Imaging : Mohd Ameenullah Khan

5 संदेश

अपनी ज़मीन पर भरोसा

लोकलुभावन घोषणाओं के बजाय कोर सेक्टर पर फोकस दर्शाता है कि सरकार जनता के बीच अपनी जमीन व भरोसे को लेकर आश्वस्त है। योगी की तारीफ में पढ़े गए सुरेश खन्ना के शेर में इसका इशारा भी था, 'वो विपरीत परिस्थितियों में चलने के आदी हैं/ मंजिल की मांग लहू से ही सजती है।'

डबल इंजन का साथ

'डबल इंजन' के फायदे भाजपा गिनाती रहती है। बजट में भी यह जुगलबंदी दिखी। पीएम आवास, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम मातृ वंदना, स्मार्ट सिटी सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं पर फोकस इसी का हिस्सा है। वित्तमंत्री ने कहा भी, 'हमने तो समंदर के रुख बदले हैं, मोदी-योगी ने सोचने के सलीके बदले हैं।'

दावों को संजीवनी

सबसे पसंदीदा निवेश डेस्टिनेशन बनाने का रास्ता बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर से ही होकर गुजरता है। बजट में इसके विस्तार पर खासा ध्यान है। 33.50 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए सेक्टोरल पॉलिसी में किए गए वादों को भी 'अर्थ' दिया गया है।

सवालों के जवाब भी

रोजगार, छुट्टा पशुओं की समस्या से जुड़े सवाल सरकार के सामने मुखर हैं। बजट में उपलब्धियां गिना इनका जवाब देने के साथ जमीनी समाधान के लिए भी खजाना खोला गया है। वह भी इस दावे के साथ, 'मेरा राजनीति से केवल इतना नाता/तुम मुझे रोकते हो अवरोध बिछाकर/मैं उसे हटाकर आगे बढ़ता जाता।'

कोर अजेंडे पर ज़ोर

हिंदुत्व व आस्था के भाजपा के कोर अजेंडे को योगी प्रदेश के विकास व पहचान से जोड़ चुके हैं। बजट में भी इसको पर्याप्त विस्तार मिला है। धार्मिक, सांस्कृतिक स्थलों व प्रतीकों की ब्रैंडिंग से संदेश साफ है कि विकास व आस्था के सरोकार सरकार व सियासत में साथ-साथ चलते रहेंगे।

इन पर भी हुई धनवर्षा

- **₹3,600** करोड़ युवाओं को टैबलेट/स्मार्टफोन के लिए
- **₹20** करोड़ से शुरू होंगे कृषि विवि में एग्रीटेक स्टार्टअप
- **₹750** करोड़ छुट्टा पशुओं की समस्या के समाधान को
- **₹2,500** करोड़ प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों के लिए
- **₹1,500** करोड़ किसानों को सिंचाई बिल पर सब्सिडी को
- **₹2,491** करोड़ 14 नए मेडिकल कॉलेजों पर खर्च होंगे
- **₹2,500** करोड़ से बेसिक-माध्यमिक स्कूलों की सूरत बदलेगी
- **₹400** करोड़ से खरीदी जाएगी 1000 नई बसें
- **₹200** करोड़ से ओडीओपी के लिए यूनिटी मॉल बनेगा
- **₹200** करोड़ से 4 नए विवि खुलेंगे

क्यों खास है यूपी का यह बजट?

■ नदीम, लखनऊ

NBT

मशहूर शायर हुए हैं आल-ए-अहमद। उनका एक शेर है - *'साहिल के सुकूं से किसे इंकार है लेकिन तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है।'*

इस शेर की प्रासंगिकता इसलिए कि योगी सरकार-2.0 का यह बजट यूपी को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रतिबद्धता दिखा रहा है। जिस मंजिल तक पहुंचने का ख्वाब देखा जा रहा है, वह है-यूपी को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाना। यह सही है कि लक्ष्य बहुत कठिन है। लेकिन किसी भी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं होता है। सफर में बहुत सारी दुश्वारियां होती हैं, बहुत सारी मजबूरियां भी, लेकिन इन सबके बीच रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने का नाम ही हिम्मत होता है और जो हिम्मत दिखाता है, कामयाबी उसके साथ खड़ी होती है। योगी सरकार ने भी हिम्मत दिखाई है और यह हिम्मत तब दिखाई है कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं हैं। एक कयास लगाया जा रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी लोकलुभावन बजट का रास्ता अख्तियार कर सकता है। लोकलुभावन बजट अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए मुफीद नहीं माना जाता है। अगर योगी सरकार यह रास्ता चुनती दिखती तो एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले लक्ष्य के प्रति कितना गंभीर है, इस पर बहस शुरू हो सकती थी, लेकिन उसने यह मौका नहीं दिया। विपक्ष को बजट रास नहीं आया है। उनके अपने तर्क हैं। लेकिन यह बात भी समझनी होगी कि विपक्ष को कभी भी, किसी भी सरकार का बजट रास नहीं आता है। यह राजनीतिक मजबूरी का हिस्सा होता है। विपक्ष को अगर सरकार के साथ ही खड़ा होना हो तो वह विपक्ष क्यों कहलाएगा, वह तो फिर सरकार के ही पाले में हुआ। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती होती है कि उसके आंगन में सभी सरकार से सहमत हों, ऐसा अनिवार्य नहीं। वैसे बजट को देखने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि राज्य किसी पार्टी का नहीं होता है। वह राज्य के एक-एक नागरिक का होता है। राज्य अगर एक कदम भी आगे बढ़ता है तो उसका सुकून हर नागरिक के हिस्से में जाता है। ना उम्मीदी को जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। जो ख्वाब देखते हैं, पूरे भी उन्हीं के होते हैं।